गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 162
दि. 11.10.2025,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

कफ सिरप से बच्चों की मौत: तमिलनाडु में जांच में लापरवाही का खुलासा, सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच ठुकराई

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश को झकझोर देने वाले जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। भारत के महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट ने तमिलनाडु की दवा जांच व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में दवाओं की टेस्टिंग और सैंपल कलेक्शन में भारी लापरवाही बरती गई, जिससे खराब गुणवत्ता वाली दवाएँ बाजार तक पहुँच गईं और निर्दोष बच्चों की जानें चली गईं।

CAG की 10 दिसंबर 2024 को जारी रिपोर्ट 'पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज' में यह पाया गया कि तमिलनाडु में ड्रग इंस्पेक्शन का लक्ष्य पूरा नहीं किया गया। वर्ष 2016-17 में जहाँ एक लाख सैंपल की टेस्टिंग का लक्ष्य था, वहाँ केवल 66,331 सैंपल की ही जांच की गई। यानी करीब 34% सैंपल की टेस्टिंग नहीं हुई। यह कमी आने वाले वर्षों में

और बढ़ती गई। 2020-21 में तो 38% टेस्टिंग कम हुई और केवल 62,358 टेस्ट ही पूरे किए गए। 2019-20 में यह कमी 40% तक पहुँच गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ड्रग इंस्पेक्टरों ने सैंपल कलेक्शन के काम में लापरवाही की और कई वर्षों में 50% से अधिक सैंपल ही नहीं जुटाए गए।

इसी लापरवाही के कारण तमिलनाडु में बनी एक दवा कोल्ड्रिफ कफ सिरप बिना पर्याप्त जांच के बाजार में पहुँची। यह सिरप मध्य प्रदेश और राजस्थान में वितरित की गई, जहाँ इसके सेवन से अब तक 25 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मृत बच्चों के परिवारों ने बताया कि सिरप देने के कुछ घंटे बाद ही बच्चों को उल्टियाँ, घबराहट और सांस लेने में तकलीफ शुरू हुई। जांच में सामने आया कि सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल जैसे जहरीले रसायन की मौजूदगी थी — वही रसायन जो शरीर में पहुँचते ही किडनी को नष्ट कर देता है।

मामले ने तूल तब पकड़ा जब देशभर में इसे लेकर विरोध और नाराजगी शुरू हुई। लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य के स्वास्थ्य विभागों की जवाबदेही पर सवाल उठाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में CBI या न्यायिक जांच की मांग की, यह कहते हुए कि यह लापरवाही की चरम सीमा है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट की CJI बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने शुक्रवार को यह याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि याचिका अखबारों में प्रकाशित खबरों पर आधारित है और याचिकाकर्ता के पास कोई ठोस दस्तावेज या सबूत नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस पर विचार करना न्यायिक रूप से उचित नहीं होगा।

इधर, इस जहरीले सिरप के निर्माता श्रीसन फार्मास्युटिकल्स का मालिक रंगनाथन को 9 अक्टूबर को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्य सरकार ने जांच के लिए SIT गठित की है, जो उत्पादन, वितरण और निरीक्षण की सभी प्रक्रियाओं की पड़ताल कर रही है। CAG रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि 2016 से 2021 के बीच तमिलनाडु में दवा परीक्षण व्यवस्था बदहाल रही है। रिपोर्ट के अनुसार, जहाँ प्रत्येक वर्ष 1,00,800 टेस्ट का लक्ष्य रखा गया, वहीं लगातार पाँच वर्षों तक उस लक्ष्य को पूरा नहीं किया गया। कई बार निरीक्षण की रिपोर्टें भी अधूरी छोड़ी गईं और रिपोर्ट जमा करने में महीनों की देरी हुई। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि दवा परीक्षण में लापरवाही का यह कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन बच्चों की मौतों ने इस व्यवस्था की असलियत को सामने ला दिया है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि यदि ड्रग क्वालिटी टेस्टिंग को लेकर सख्त निगरानी नहीं रखी गई, तो ऐसी घटनाएँ फिर दोहराई जा सकती हैं।

बच्चों की मौतों से गमगीन परिवार अब भी इंसाफ की राह देख रहे हैं। छिंदवाड़ा की एक माँ ने कहा — "हमने तो सोचा था खाँसी की दवा दे रहे हैं, पर वही जहर बन गई। हमें किसी का नाम नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि किसी और माँ की गोद सूनी न हो।"

यह घटना केवल एक सिरप या एक कंपनी की गलती नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की चेतावनी है — कि जब जांच की चूक होती है, तब उसका असर सीधे जीवन पर पड़ता है। सवाल यह नहीं कि कितने सैंपल जांचे गए, बल्कि यह है कि कितने बच्चों की जान उस लापरवाही के कारण चली गई, जिनकी जिम्मेदारी किसी कागज़ में नहीं लिखी गई।

पाकिस्तान में तीन कबायली नेताओं का अपहरण कर हत्या, टीटीपी आतंकियों की बर्बर करतूत

(जीएनएस)। नई दिल्ली। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवाद एक बार फिर बेकाबू हो गया है। शुक्रवार को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़े आतंकवादियों ने तीन कबायली नेताओं का अपहरण कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। अधिकारियों के अनुसार, यह घटना लक्की मरवत जिले की है, जहां गुरुवार को तीनों नेताओं को उनके घरों से अगवा किया गया था। मारे गए सभी नेता बेतानी जनजाति से संबंध रखते थे और मरवत बेतानी कौमी तहरीक नामक संगठन से जुड़े थे, जो स्थानीय मरवत और बेतानी पश्तून जनजातियों के अधिकारों और सामाजिक मुद्दों के लिए आवाज उठाता रहा है। बताया गया कि अपहरण के बाद आतंकियों ने मध्यस्थों के माध्यम से यह भरोसा दिलाया था कि तीनों नेताओं को सुरक्षित रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन इसके विपरीत, उन्हें पहले गंभीर शारीरिक यातनाएँ दी गईं और बाद में बेरहमी से हत्या कर दी गई। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, तीनों के शव बन्नू जिले के तोची पुल के पास फेंके मिले, जिन पर यातना के स्पष्ट निशान थे। यह इलाका पहले भी टीटीपी की गतिविधियों का गढ़ माना जाता रहा है। स्थानीय प्रशासन ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इलाके में सुरक्षा बलों का गश्त बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि टीटीपी के आतंकवादी अक्सर ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं, जिन पर उन्हें शक होता है कि वे सरकारी एजेंसियों के लिए जासूसी कर रहे हैं। कई बार इन्हें अपहरण कर पूछताछ के नाम पर यातनाएँ दी जाती हैं और फिर मौत के घाट उतार दिया जाता है। बता दें कि नवंबर 2022 में टीटीपी ने पाकिस्तान सरकार के साथ हुए संघर्ष विराम को तोड़ दिया था। तब से लेकर अब तक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में आतंकवादी हमलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस, सेना और सरकारी अधिकारियों पर हमले आम हो चुके हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरकार की आतंकवाद विरोधी नीति पूरी तरह विफल हो चुकी है और जनजातीय इलाकों में प्रशासनिक नियंत्रण लगभग नाममात्र रह गया है। इ

आईपीएस पूरण कुमार आत्महत्या मामला: चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी करेगी जांच, पत्नी ने एफआईआर पर उठाए सवाल

(जीएनएस)। चंडीगढ़। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एडीजीपी वाई पूरण कुमार की आत्महत्या के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। अब इस संवेदनशील प्रकरण की जांच चंडीगढ़ पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) करेगी। चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में छह सदस्यीय टीम गठित की गई है, जो पूरे मामले की तहकीकात करेगी। इस घटना ने न केवल पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है, बल्कि प्रशासनिक गलियारों में भी सनसनी फैला दी है। आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार ने बीते गुरुवार को चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास में आत्महत्या कर ली थी। चंडीगढ़ पुलिस ने देर रात सुसाइड नोट के आधार पर मामला दर्ज किया था, लेकिन अब मृतक की पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने दर्ज एफआईआर पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस की महिला एसएसपी कंवरदीप कौर को पत्र लिखकर कहा है कि एफआईआर अधूरी है और इसमें कई अहम बिंदुओं को शामिल नहीं किया गया।

इस बीच, मृतक अधिकारी के परिजन अब भी पोस्टमार्टम करवाने से इंकार कर रहे

हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक हरियाणा के डीजीपी और रोहतक के एसपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वे अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं देंगे। मृतक के भाई, जो विदेश से लौटे हैं, और आईएएस अधिकारी डी सुरेश ने शुक्रवार को चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय में डीजीपी डॉ. सागर प्रीत हुड्डा से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच तभी संभव है जब उच्च अधिकारियों की भूमिका की भी पड़ताल की जाए। डीजीपी हुड्डा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जांच पूरी पारदर्शिता से होगी और इसी उद्देश्य से आईजी स्तर की एसआईटी गठित की गई है।

घटना के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और गृह सचिव सुमिता मिश्रा शुक्रवार को मृतक की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार से मिलने उनके सेक्टर-24 स्थित आवास पर पहुंचे। करीब डेढ़ घंटे चली इस मुलाकात में दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने परिवार को संवेदना दी और कहा कि सरकार पूरी ईमानदारी से जांच करवाएगी। इस दौरान आईएएस अधिकारी राज शेखर वुडरू भी उपस्थित रहे। राजनीतिक स्तर पर भी इस प्रकरण ने जोर पकड़ लिया है। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने अमनीत पी कुमार से मुलाकात के बाद कहा कि एडीजीपी की आत्महत्या के पीछे गंभीर कारण हैं, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लीपा-पोती कर रही है और निष्पक्ष जांच से बच रही है। वहीं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गीता भुक्कल ने भी सरकार की निंदा की और कहा कि अब तक की चुप्पी से लगता है कि सत्ता के दबाव में कार्रवाई रोकी जा रही है।

उधर, बढ़ते तनाव और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने आईएएस अमनीत पी कुमार के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। सेक्टर-24 स्थित सरकारी आवास के बाहर अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 24 घंटे निगरानी के आदेश दिए गए हैं।

एडीजीपी वाई पूरण कुमार की आत्महत्या ने पूरे पुलिस महकमे को झकझोर दिया है। एक ओर परिवार न्याय की मांग कर रहा है, दूसरी ओर पुलिस विभाग पर सवालों की बौछार हो रही है। अब सबकी निगाहें आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अगुवाई वाली एसआईटी पर टिकी हैं, जो आने वाले दिनों में इस रहस्यमय मामले की असल सच्चाई सामने ला सकती है।

सरकारी बैंकों में अब निजी क्षेत्र के अफसर भी बन सकेंगे एमडी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। बैंकिंग क्षेत्र में सरकार ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के शीर्ष प्रबंधन पदों के द्वार निजी क्षेत्र के अधिकारियों के लिए खोल दिए। अब भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) समेत देश के सभी प्रमुख सरकारी बैंकों में निजी क्षेत्र के योग्य अधिकारी भी प्रबंध निदेशक (एमडी) बन सकेंगे। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, एसबीआई में एमडी के चार पदों में से एक पद अब निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों के लिए आरक्षित रहेगा। इससे पहले ये सभी पद केवल बैंक के भीतर से ही भरे जाते थे।

नए नियमों के तहत अब 11 अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी यही व्यवस्था लागू होगी। इनमें पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं। सरकार का मानना है कि निजी क्षेत्र के अनुभवी प्रबंधकों के आने से बैंकिंग प्रणाली में नवाचार, प्रतिस्पर्धा और पेशेवर दक्षता बढ़ेगी।

नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, निजी क्षेत्र के उम्मीदवार को एमडी पद के लिए पात्र माने जाने के लिए कम से कम 21 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, जिसमें 15 वर्ष बैंकिंग का और कम से कम दो वर्ष किसी बैंक बोर्ड के बोर्ड स्तर पर कार्य का अनुभव शामिल होगा। निजी क्षेत्र से चयनित व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में उसी वेतनमान और सेवा शर्तों पर कार्य करेंगे जो वर्तमान एमडी के लिए लागू हैं।

इसी तरह, कार्यकारी निदेशक (ईडी) पद के लिए भी अब निजी क्षेत्र के अधिकारी आवेदन कर सकेंगे। इस पद के लिए न्यूनतम 18 वर्ष का अनुभव आवश्यक है, जिसमें 12 वर्ष बैंकिंग क्षेत्र का और 3 वर्ष उच्च प्रबंधकीय स्तर पर होना चाहिए। बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो (BBB) की अनुशंसा के बाद इन नियुक्तियों पर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) करेगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि एसबीआई में इन नियमों के लागू होते ही एमडी का एक पद रिक्त माना जाएगा, ताकि उसी से इस नई नीति की शुरुआत की जा सके। इसके बाद बनने वाली रिक्तियों को आंतरिक उम्मीदवारों से भरा जाएगा। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यकारी निदेशक के चार पदों में से एक पद निजी क्षेत्र सहित सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए खुला रहेगा।

सरकार के इस निर्णय को बैंकिंग सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक सोच और सार्वजनिक क्षेत्र की विश्वसनीयता का समावेश होगा। लंबे समय से चर्चा में रही "पब्लिक-प्राइवेट लीडरशिप" की अवधारणा अब भारतीय बैंकिंग सेक्टर में साकार होती दिख रही है। इससे भविष्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कार्यकुशलता और निवेश आकर्षण में भी उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद जताई

अमेरिका ने दो भारतीयों सहित 50 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध, ईरान को ऊर्जा व्यापार में मदद का आरोप

(जीएनएस)। वाशिंगटन। अमेरिका ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो भारतीय नागरिकों समेत दुनिया की 50 कंपनियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने बताया कि इन कंपनियों और व्यक्तियों ने ईरान के तेल और गैस उत्पादों के अवैध निर्यात में मदद की, जिससे तेहरान को अरबों डॉलर की आमदनी हुई। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह धनराशि बाद में उन आतंकवादी संगठनों तक पहुंचाई गई, जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए खतरा पैदा करते हैं।

अमेरिकी वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद, कई निजी और शिपिंग कंपनियाँ गुप्त रूप से ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री और परिवहन में शामिल हैं। इस नेटवर्क का खुलासा लंबे समय से चल रही खुफिया निगरानी के बाद हुआ।

प्रतिबंधित भारतीय नागरिकों में वरुण पूला और सोनिया श्रेष्ठा शामिल हैं। वरुण पूला मार्शल द्वीप स्थित बर्था शिपिंग इंक के मालिक हैं। उनकी कंपनी कोमोरोस झंडे वाले जहाज पामिर का संचालन करती है, जिसने जुलाई 2024 से अब तक चीन तक लगभग 40 लाख बैरल ईरानी एलपीजी (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) पहुंचाई है। वहीं, सोनिया श्रेष्ठा वेगा स्टार शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की मालिक हैं। उनका पोत नेप्टा भी कोमोरोस के झंडे तले संचालित होता है

और जनवरी 2025 से लगातार पाकिस्तान को ईरान से एलपीजी भेज रहा है।

अमेरिका ने कहा कि प्रतिबंधों के तहत इन व्यक्तियों और कंपनियों की अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी संपत्तियाँ जब्त कर ली जाएंगी। साथ ही जिन कंपनियों में इनकी हिस्सेदारी 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, उन्हें भी स्वतः प्रतिबंधित सूची में शामिल कर दिया जाएगा।

वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ईरान ने वैश्विक प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए छद्म कंपनियों, झूठे शिपिंग दस्तावेजों और "शिप-टू-शिप ट्रांसफर" तकनीक का इस्तेमाल किया। इन गतिविधियों में एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप की कई कंपनियाँ भी शामिल हैं।

अमेरिका ने यह भी चेतावनी दी कि ईरान की ऊर्जा सप्लाई चेन से जुड़े किसी भी व्यक्ति, बैंक या जहाज पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाशिंगटन ने साफ कहा कि उसका उद्देश्य ईरान की अर्थव्यवस्था के उस हिस्से को निशाना बनाना है, जो आतंकवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देता है।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर संबंध पहले से ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इस ताज़ा प्रतिबंध से एशियाई ऊर्जा व्यापार पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि कई देश अप्रत्यक्ष रूप से ईरानी ईंधन पर निर्भर हैं।

देशभर में वोटर लिस्ट का विशेष सत्यापन करवाएगा चुनाव आयोग, पहले चरण में पांच राज्यों में होगी शुरुआत

नई दिल्ली। बिहार में मतदाता सूची के विशेष सत्यापन (Special Intensive Revision - SIR) अभियान के बाद अब चुनाव आयोग ने पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से यह प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के अनुसार, पहले चरण की शुरुआत उन राज्यों से होगी जहां अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी शामिल हैं।

चुनाव आयोग का यह कदम देशभर में मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। आयोग के अनुसार, SIR अभियान के दौरान मतदाता सूची की घर-घर जाकर जांच की जाएगी। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई मृत व्यक्ति, स्थानांतरित मतदाता या विदेशी नागरिक वोटर लिस्ट में शामिल न रहे। साथ ही, नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे और पते या विवरण में हुई गलतियों को सुधारा जाएगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत की हर मतदाता सूची पारदर्शी, अद्यतन और सटीक हो। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में SIR शुरू करने की तैयारियाँ चल रही हैं और इसकी तिथियों का अंतिम निर्णय चुनाव आयोग की बैठक में लिया जाएगा।

गौरतलब है कि बिहार में हाल ही में संपन्न SIR अभियान के बाद हजारों फर्जी मतदाता नाम सूची से हटाए गए थे। चुनाव आयोग ने पाया कि कई जगहों पर एक ही व्यक्ति के नाम दो या तीन अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत थे।

संपादकीय

रिश्तों में नई ऊर्जा

ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने निरंकुश टैरिफ थोपने व भारत के हितों पर कुठाराघात की नीति अख्तियार की हुई है, ब्रिटेन के साथ रक्षा व कारोबारी रिश्तों में नई शुरुआत उम्मीद जगाने वाली है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते का सिरे चढ़ना दोनों पक्षों के हित में बताया जा रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा को नई दिल्ली और लंदन के संबंधों में एक नये सिरे से बदलाव का प्रतीक बताया जा रहा है। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात के प्रतीकात्मक और व्यावहारिकता की दृष्टि से गहरे निहितार्थ हैं। इस यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण समझौते इस यात्रा के महत्व को रेखांकित करते हैं। जिसमें 468 मिलियन डॉलर का मिसाइल सौदा, मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए के शीघ्र क्रियान्वयन के लिये प्रतिबद्धता तथा भारत में नौ ब्रिटिश विश्वविद्यालय खोलने पर सहमत होना शामिल है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि इस रिश्ते में 'एक नई ऊर्जा है', जो व्यापार, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा का समन्वय चाहती है। हालांकि, मुक्त व्यापार समझौते का मूल्यांकन, इसके प्रतीकात्मक मूल्य के बजाय इसके वास्तविक आर्थिक प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए। मुक्त व्यापार समझौते के क्रियान्वयन के बाद भारत के लिये ब्रिटिश बाजार तक भारतीय कपड़ों, दवा और सेवाओं, विशेष रूप से आईटी और फिनटेक के निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मुक्त व्यापार समझौते के क्रियान्वयन को लेकर कुछ चिंताएं भी मौजूद हैं। मसलन छोटे और मध्यम उद्यमों के सामने सस्ते ब्रिटिश आयातों से कमजोर होने या नियामक विषमताओं का सामना करने की आशंका बनी हुई है। इसमें दो राय नहीं है कि एफटीए के फलस्वरूप, ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन के लिये, भारत एक अनिश्चित वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच विकास का एक लाभप्रद अवसर और एक स्थिर अर्थव्यवस्था वाला मजबूत साझेदार का मिलना है। लेकिन इसके बावजूद मुक्त व्यापार समझौते के क्रियान्वयन में भारतीय हितों की रक्षा के लिये सतर्क पहल की जरूरत भी महसूस की जा रही है। वैसे यह भी तथ्य है कि अनुसंधान, डिजिटल नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा में पारस्परिक निवेश की कसौटी पर ही दोनों देशों के रिश्तों की असली परीक्षा होगी। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि भारतीय पेशेवरों या छात्रों के लिए वीजा मानदंडों में ढील देने से स्टारमर का स्पष्ट इनकार करना इस बहुप्रचारित साझेदारी की सार्थकता को लेकर सवाल पैदा कर सकता है। यह विडंबना ही है कि ब्रिटेन कुछ मुद्दों को लेकर दोहरा मापदंड अपना रहा है। एक ओर ब्रिटेन जहां भारतीय बाजार में अपनी पहुंच बनाना और साथ ही तकनीकी सहयोग तो पाना चाहता है, लेकिन वहीं वह श्रम की गतिशीलता को लेकर सतर्क बना हुआ है, जो कि ब्रिटेन के साथ भारत के आर्थिक और शैक्षिक जुड़ाव का एक केंद्रीय मुद्दा बना रहा है। इस बात में दो राय नहीं हो सकती है कि यदि प्रतिभाओं का आदान-प्रदान एकतरफा ही रहेगा, तो पारस्परिक लाभ पर साझेदारी फल-फूल नहीं सकती। निर्विवाद रूप से यह तथ्य तार्किक है कि मुक्त व्यापार समझौते की राह अभी भी बाधाओं से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पायी है। उल्लेखनीय है कि टैरिफ, बौद्धिक संपदा और श्रम गतिशीलता के मुद्दे पर मतभेद अभी भी बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर मूल्य आधारित कूटनीति पर भारतीय प्राथमिकता को लेकर दोनों देशों में मतभेद सामने आ सकते हैं। साथ ही यह भी जरूरी है कि दोनों पक्षों को पुरानी कसक से प्रेरित कूटनीति से आगे बढ़ने की जरूरत होगी। निर्विवाद रूप से विशेष संबंध औपनिवेशिक हैंगओवर या प्रवासी भावना पर आधारित नहीं हो सकते। इस साझेदारी का वायदा एक ऐसे सतत सहयोग के निर्माण में निहित है, जिसमें दोनों देशों के आम नागरिकों को वास्तविक लाभ मिल सके। भारत की चिंता ब्रिटेन की भूमि से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले तत्वों पर अंकुश लगाने को लेकर भी है। निश्चय ही अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब अराजकता नहीं हो सकता। हाल के दिनों में कुछ अप्रिय घटनाएं भारतीय लोकतंत्र के प्रतीकों पर प्रहार करने के रूप में सामने आ चुकी हैं।

भारतीय विदेश नीति के 'संतुलन' की परीक्षा

> "अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान के बीच बदलते समीकरणों के दौर में भारत की विदेश नीति नए संतुलन की परीक्षा से गुजर रही है, जहां आने वाले वर्षों में निर्णायक मोड़ संभव है।

इस साल पहले टैरिफ और फिर 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर अमेरिकी रुख में आए बदलाव पर भारत की ओर से कोई तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई, पर देश में आक्रोश की लहर थी। शुरू में समझ नहीं आता था, पर अब धीरे-धीरे लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच, पिछले दो दशक से चली आ रही सौहार्द-नीति में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है। कुछ वर्षों से यह सवाल किया जा रहा है कि भारत एक तरफ रूस और चीन और दूसरी तरफ अमेरिका के बीच अपनी विदेश-नीति को किस तरह संतुलित करेगा? इसे स्पष्ट करने की घड़ी अब आ रही है।

भारत ने तालिबान, पाकिस्तान, चीन और रूस के साथ मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अफ़ग़ानिस्तान स्थित बगराम एयरबेस पर कब्ज़ा करने के प्रयास का विरोध किया है। यह अप्रत्याशित घटना तालिबान के विदेशमंत्री आमिर ख़ान मुत्तक़ी की भारत-यात्रा से कुछ दिन पहले हुई है। अफगानिस्तान पर मॉस्को प्रारूप परामर्श के प्रतिभागियों द्वारा मंगलवार को जारी संयुक्त बयान में बगराम का नाम लिए बिना यह बात कही गई।

अफ़ग़ानिस्तान पर मॉस्को प्रारूप परामर्श की सातवीं बैठक मॉस्को में अफ़ग़ानिस्तान, भारत, ईरान, क़ज़ाक़िस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के विशेष प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर आयोजित की गई थी। बेलारूस का एक प्रतिनिधिमंडल भी अतिथि के रूप में बैठक में शामिल हुआ। इस बैठक में 'पहली बार विदेशमंत्री अमीर खान मुत्तकी के नेतृत्व में अफगान प्रतिनिधिमंडल ने भी सदस्य के रूप में भाग लिया।

इसके पहले ट्रंप ने कहा था कि तालिबान, देश के बगराम एयर बेस को वाशिंगटन को

सौंप दें। सच यह है कि ट्रंप ने ही पांच साल पहले तालिबान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसने काबुल से अमेरिका की वापसी का रास्ता साफ किया था। पिछली 18 सितंबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, 'हमने इसे तालिबान को मुफ्त में दे दिया। अब हमें वह अड्डा वापस चाहिए।' बहरहाल, तालिबान के विदेशमंत्री की मेज़बानी की तैयारी कर रहे भारत ने ट्रंप की योजना का विरोध करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हालांकि हमने अभी तक तालिबान शासित अफ़ग़ानिस्तान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, पर धीरे-धीरे संबंध स्थापित कर लिए हैं। संयुक्त वक्तव्य में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, 'क्षेत्रीय संपर्क प्रणाली में अफगानिस्तान के सक्रिय एकीकरण का हम समर्थन करते हैं।' भारत के नज़रिए से अमेरिका के लिए यह एक संदेश है, जिसने ईरान में चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंधों में छूट हटा ली है, जिसका इस्तेमाल भारत के अफगानिस्तान से संपर्क के लिए किया जाता रहा है।

इस घटनाक्रम के समांतर कुछ और बातों पर गौर करें। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यक्तिगत रूप से मधुर संबंध बना लिए हैं। हाल में उन्होंने ट्रंप के सामने अरब सागर में एक बंदरगाह बनाने और उसे चलाने का प्रस्ताव पेश किया है। यह बंदरगाह बलोचिस्तान के ग्वादर जिले के एक शहर पासनी में होगा, जो ईरान में भारत द्वारा विकसित किए जा रहे चाबहार बंदरगाह के एकदम करीब होगा। पिछले महीने पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ बंद कमरे में बैठक की थी। अब खबर है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को कुछ खनिजों की खेप भेजी है। उनका कहना है कि हम अमेरिका को रेअर अर्थ जैसे खनिज दे सकते हैं, जिनकी अमेरिका को बड़ी ज़रूरत है। हाल में एक और खबर आई है। अमेरिका ने पाकिस्तान को दो नए हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। ये हैं नवीनतम एम-120सी-8 और डी-3 एमरैम मिसाइलें। पाकिस्तान ने 2019 में अभिनंदन वर्धमान के विमान पर एमरैम मिसाइल ही दागी थी।

पता नहीं अमेरिका पासनी में बंदरगाह बनाएगा या नहीं, पर इन रिश्तों की जटिलता को समझने के लिए चीन को भी शामिल करना होगा। सवाल केवल भारत का ही नहीं है, बल्कि यह भी है कि पाकिस्तान अब अमेरिका और चीन के साथ रिश्तों को किस तरह निभाएगा? क्या वह चीन से दूर हो जाएगा? क्या अमेरिका भी चीन के साथ सामरिक रिश्तों में सुधार कर रहा है? अभी तक वह सीपैक और ग्वादर का विरोध करता था, क्या वह अब ग्वादर को स्वीकार कर लेगा?

इसके साथ ही एक सैद्धांतिक प्रश्न भी सामने आया है। हाल में अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को फिर से तराजू पर बराबरी से तोलना शुरू कर दिया है। एक दशक पहले उसने भारत और पाकिस्तान को 'डिहाइफ़नेट' करने की नीति बनाई थी, जिससे वह बराबरी खत्म हो गई थी, पर अब वह नीति खत्म हो रही है और पुरानी नीति वापस आ रही है। हाल में जेएनयू में हुए अरावली शिखर सम्मेलन में विदेशमंत्री एस जयशंकर ने ऐसे सवालों के कुछ दिलचस्प स्पष्टीकरण दिए हैं।

जयशंकर ने 'डिहाइफ़नेशन' की अवधारणा पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा, हम पड़ोसियों की चुनौती से बच नहीं सकते, चाहे वास्तविकता कितनी भी अप्रिय क्यों न हो। सबसे अच्छा रास्ता यही है कि भारत शक्ति और क्षमता के मामले में दूसरे पक्ष से आगे निकले। यानी कि भारत की ताकत, अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव में वृद्धि इतनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए कि ऐतिहासिक समानता या तुलना प्रासंगिक न रहे। वर्ष 1970 के दशक में भारत-पाकिस्तान की समतुल्यता को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जाता था। अब कोई भी इस तरह की बात नहीं करता। कुछ देश क्षेत्रीय तनावों का फायदा उठाने या अपने फायदे के लिए भारत को अन्य शक्तियों के साथ 'संतुलित' करने की कोशिश करते हैं।

उन्होंने अमेरिका और चीन के अलग-अलग दृष्टिकोणों का उल्लेख किया : अमेरिका साझेदारी में राष्ट्रीय हितों से प्रेरित है, जबकि चीन संक्रमणकालीन दौर से गुज़र रहा है जहां उसके दृष्टिकोण पूरी तरह से स्थापित नहीं हुए हैं। उधर यूरोप में भू-राजनीतिक संतुलन में आए बदलावों की ओर भी ध्यान दें, जहां अमेरिका-रूस-चीन सुरक्षा और व्यापार को लेकर पहले की स्थिर व्यवस्थाएं अब बदल रही हैं।

इन सब बातों के साथ ही पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया की बात पर ध्यान दें, जिन्होंने हाल में एक कॉन्क्लेव में कहा, डोनाल्ड ट्रंप अंततः इस्लामाबाद से निराश हो जाएंगे और वर्तमान में संबंधों में जो गर्मजोशी दिख रही है, वह जल्द ही खत्म हो जाएगी। उनके अनुसार चीन की शह पर पाकिस्तान वैश्विक पहुंच और अमेरिका के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत से यह बात साफ़ ज़ाहिर होती है कि चीन उसका 'मुख्य गॉडफादर' है।

पाकिस्तान अभी चीन और अमेरिका के साथ इन जटिल लेन-देनों को संभाल रहा है, लेकिन समय के साथ इस संतुलन को बनाए रखना उसके लिए और भी मुश्किल होगा। बहरहाल भारतीय विदेशनीति के संतुलनकारी पक्ष की इस समय परीक्षा है। आने वाले समय में भारत को चीन, अमेरिका और रूस तीनों के प्रतिस्पर्धी के रूप में उभरना है। यह काम अगले दस वर्षों में होगा। इसलिए आज की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रेरणा

मनुष्य होने का अर्थ

वनवास के दिनों में जब पांडव अपने कर्मों और भाग्य के बीच संतुलन साधते हुए वन में निवास कर रहे थे, तब एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने न केवल उनके जीवन की दिशा बदल दी, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए धर्म का मर्म उजागर कर दिया। यह वह क्षण था जब युधिष्ठिर का संवाद यक्ष से हुआ—एक ऐसा संवाद जो केवल प्रश्नोत्तर नहीं था, बल्कि मानवता के अस्तित्व का गूढ़ रहस्य था।

उस दिन भीषण गर्मी थी। प्यास से व्याकुल पांडवों ने एक झील देखी। सहदेव सबसे पहले जल लेने गया, परंतु जब उसने झील के समीप एक अदृश्य यक्ष का स्वर सुना—"हे वीर, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी जल पी सकोगे"—तो उसने उस वाणी की उपेक्षा की और जल पीने लगा। किंतु अगले ही क्षण वह भूमि पर गिर पड़ा, निर्जीव। एक-एक कर नकुल, अर्जुन और भीम भी गए, सबका वही हाल हुआ। अंततः स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर वहाँ पहुँचे। उन्होंने अपने चारों भाइयों को मृतप्राय देखकर भी धैर्य नहीं खोया। उन्होंने जल लेने से पहले यक्ष की आज्ञा स्वीकार की और कहा, "हे देव, प्रश्न पूछो, मैं उत्तर दूँगा।"

तभी प्रारंभ हुआ वह दिव्य संवाद—जहाँ प्रश्न साधारण थे, पर उत्तर मानव जीवन की आत्मा को छूने वाले थे।

यक्ष ने पहला प्रश्न किया—"हे युधिष्ठिर, कौन व्यक्ति शोक नहीं करता?" युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिया—"जिसका मन नियंत्रण में होता है, वही शोक नहीं करता। जो अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके लिए न हानि दुख है, न लाभ सुख। नियंत्रित मन ही मोक्ष का द्वार है।" यह उत्तर सुनकर यक्ष विस्मित रह गया, क्योंकि युधिष्ठिर ने एक ही वाक्य में समूचे योग दर्शन का सार कह दिया था। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी संसार नहीं, उसका अस्थिर मन है। जिसने मन पर विजय पा ली, उसने जगत पर विजय पा ली।

फिर यक्ष ने पूछा—"किसकी मित्रता कभी क्षीण नहीं होती?" युधिष्ठिर ने उत्तर दिया—"सज्जन और संस्कारी मनुष्यों की मित्रता कभी क्षीण नहीं होती। वे संबंधों को स्वार्थ या लाभ से नहीं जोड़ते, बल्कि हृदय की सच्चाई से निभाते हैं।" यह उत्तर आज भी उतना ही सत्य है जितना उस युग में था। स्वार्थ से जुड़ी मित्रता मिट जाती है, पर आत्मा से जुड़ी मित्रता अमर रहती है। मानव धर्म का दूसरा आधार यहीं प्रकट हुआ—निष्ठा और सच्चाई।

फिर यक्ष ने पूछा—"धरती से भारी और आकाश से ऊँचा क्या है?" युधिष्ठिर ने गहरी भावनाओं से कहा—"धरती से भारी है मां की ममता और आकाश से ऊँचा है पिता का अरमान। माता वह है जो अपने बच्चे के लिए सारे कष्ट सहकर भी मुस्कराती है, और पिता वह है जो अपनी संतान को अपने से आगे बढ़ते देखना चाहता है।" यह उत्तर सुनकर यक्ष की आँखों में भी श्रद्धा झलक उठी। यह वह क्षण था जब धर्मराज ने धर्म को भावनाओं के रूप में व्यक्त किया—जहाँ माता-पिता के प्रति कृतज्ञता ही सबसे बड़ा कर्म बन जाती है।

यक्ष ने फिर कहा—"हे धर्मराज, तुम्हारे उत्तर गहन हैं। बताओ, सच्चा मानव धर्म क्या है?" युधिष्ठिर ने उत्तर दिया—"मानव धर्म किसी पुस्तक में नहीं लिखा, वह तो मनुष्य के आचरण में बसता है। जो दूसरों के दुःख को अपना दुःख समझे, जो बिना स्वार्थ के सहायता करे, जो सत्य बोले और अपने मन पर संयम रखे—वही सच्चा धर्मात्मा है। जो केवल पूजा करता है पर करुणा नहीं रखता, वह धर्म का नहीं, केवल आडंबर का अनुयायी है। सच्चा धर्म प्रेम है, क्षमा है, और आत्मसंयम है।"

इन उत्तरों से यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा—"हे युधिष्ठिर, तुमने धर्म का सार बता दिया है। तुम्हारे भीतर जो सत्य और समत्व है, वही मानवता की पहचान है। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देता हूँ—तुम्हारे सभी भाई पुनर्जीवित हो जाएँगे।"

क्षणभर में सहदेव, नकुल, भीम और अर्जुन उठ खड़े हुए। जल की लहरों में जैसे पुनर्जन्म की ध्वनि गूंज उठी। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा—"हे देव, यह आपका आशीर्वाद नहीं, बल्कि धर्म का प्रतिफल है। जिसने धर्म को समझ लिया, उसके लिए मृत्यु भी असहाय है।"

उस दिन से युधिष्ठिर और यक्ष का यह संवाद मानव जीवन का आधार बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य का असली धर्म कोई बाहरी परंपरा नहीं, बल्कि उसकी भीतरी शुद्धता है। जब मनुष्य अपने भीतर के लोभ, क्रोध और अहंकार को जीतकर सत्य, करुणा और कर्तव्य को अपनाता है, तभी वह ईश्वर के समीप पहुँचता है।

युधिष्ठिर ने हमें यह सिखाया कि मानव होना मात्र शरीर धारण करना नहीं, बल्कि भावनाओं, विवेक और प्रेम के संतुलन में जीना है। यही मनुष्य होने का अर्थ है—"जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है, जो अपने मन को जीतता है, और जो हर जीव में ईश्वर का अंश देखता है—वही सच्चे अर्थों में मानव कहलाता है।"

General से Jawan तक एक कसौटी, Indian Army ने बनाई नई Fitness Policy, साल में सबको दो बार देना होगा Combined Physical Test

भारतीय सेना ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि अब से केवल जवान ही नहीं, बल्कि ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल जैसे शीर्ष अधिकारी भी हर वर्ष दो बार शारीरिक फिटनेस परीक्षण देंगे। यह संयुक्त शारीरिक परीक्षण (Combined Physical Test-CPT) अगले वर्ष अप्रैल से लागू होगा और इसका उद्देश्य है "फिटनेस को रैंक से ऊपर रखकर युद्धक तैयारी को नया आयाम देना।"

हम आपको बता दें कि अब तक सेना में दो अलग-अलग मानक थे। युद्धक शारीरिक दक्षता परीक्षा (BPET), 45 वर्ष तक के सैनिकों और अधिकारियों पर लागू थी। तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा (PPT) 50 वर्ष तक के अधिकारियों पर लागू थी। अब इन दोनों को मिलाकर एक ही प्रणाली बनाई गई है— CPT (Combined Physical Test)। इसमें उम्र की ऊपरी सीमा 60 वर्ष कर दी गई है। इसका अर्थ है कि अब शीर्ष तीन-सितारा अधिकारी तक इस दायरे में आएंगे।

Combined Physical Test में क्या-क्या शामिल है, इस पर गौर करें तो आपको बता दें कि 3.2 किलोमीटर दौड़ (या तेज चाल) 4.5 किलो वजन के साथ, पुश-अप्स, सिट-अप्स और रस्सी चढ़ना। हर प्रतिभागी को न्यूनतम 6 ग्रेड प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसकी पदोन्नति पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, 55 वर्ष तक अधिकारी "निगरानी में" यह परीक्षण देंगे और उसके बाद 60 वर्ष तक "स्व-मूल्यांकन" के आधार पर फिटनेस की पुष्टि करेंगे।

देखा जाये तो सेना का यह फैसला केवल शारीरिक कसौटी का विस्तार नहीं, बल्कि नेतृत्व दर्शन में बदलाव का संकेत है। आधुनिक युद्ध का स्वरूप भले तकनीक-प्रधान हो गया हो, परंतु "मानवीय तत्व" उसकी आत्मा बना हुआ है। एक वरिष्ठ अधिकारी जो स्वयं मैदान में शारीरिक रूप से सक्षम है, वही अपने जवानों में आत्मविश्वास और अनुशासन की भावना जगा सकता है। यह निर्णय सेना के उस सिद्धांत को पुनः पुष्ट करता है कि "नेतृत्व का अर्थ आदेश देना नहीं, बल्कि उदाहरण बनकर नेतृत्व करना है।" सेना के दस्तावेज़ में भी यही भाव है कि कमांडर को "हर समय अग्रिम मोर्चे पर टीम का नेतृत्व करने में सक्षम होना चाहिए।" अर्थात, यह कदम सेना के नेतृत्व में शारीरिक विश्वसनीयता और नैतिक अधिकार दोनों को पुनर्स्थापित करता है।

देखा जाये तो आज के युद्धक्षेत्र का स्वरूप पहले जैसा नहीं रहा। यह अब केवल "शक्ति के टकराव" का नहीं, बल्कि "सहनशक्ति और तत्परता" का युद्ध है। हाइब्रिड वॉरफेयर, मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस, काउंटर-इंसर्जेंसी और सीमित संसाधनों में त्वरित प्रतिक्रिया, इन सबके लिए सैनिक का शारीरिक और मानसिक रूप से उच्चतम स्तर पर रहना आवश्यक है। डिजिटलाइजेशन और ड्रोन-आधारित युद्धक प्रणालियों के बावजूद, 'मानव शरीर' ही हर सैन्य अभियान का केंद्रबिंदु है। इसलिए सेना का यह फैसला केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से आवश्यक कदम है।

सेना दस्तावेज़ के शब्दों पर गौर करें तो इसमें कहा गया है, "ताकत, सहनशक्ति और चपलता युद्ध की तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।" "चुस्त-दुरुस्त सैनिक अपनी यूनिट के लिए अधिक सक्षम, विश्वसनीय और प्रभावी भूमिका में होता है।" यह बात केवल जवान पर नहीं, बल्कि शीर्ष नेतृत्व पर भी समान रूप से लागू होती है।

सेना ने दो अलग-अलग प्रणालियों को समाप्त कर एकीकृत CPT लागू किया है तो इसका अर्थ है संचालनात्मक एकरूपता (Operational Simplification)। अब रैंक, आयु या लिंग के अनुसार अलग-अलग मानक नहीं होंगे, बल्कि एक समन्वित तालिका होगी, जो सभी को समान मापदंडों पर परखेगी। इससे दो प्रमुख लाभ होंगे। पहला- अब फिटनेस का मूल्यांकन स्पष्ट, तुलनीय और निष्पक्ष होगा। दूसरा- अलग-अलग परीक्षणों की जगह एकीकृत प्रणाली अपनाने से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। यह सुधार केवल "शारीरिक फिटनेस" नहीं बल्कि "संस्थागत फिटनेस" का भी प्रतीक है, यानी एक ऐसी सेना जो खुद को बदलते समय के अनुसार ढालने की क्षमता रखती है।

हम आपको यह भी बता दें कि भारतीय सेना ने हाल के वर्षों में कई सुधार आरंभ किए हैं। अग्निपथ योजना के ज़रिए जवानों की औसत आयु घटाकर युवा प्रोफ़ाइल बनाई गई, थियेटर कमांड संरचना की दिशा में कदम बढ़ाए गए और अब यह फिटनेस का आधुनिकीकरण उसी प्रक्रिया का अगला चरण है। इससे यह संदेश जाता है कि भारतीय सेना न केवल हथियारों से, बल्कि मानवीय गुणवत्ता और आत्म-अनुशासन से भी युद्धक क्षमता बढ़ा रही है। यह कदम सैन्य नैतिकता में भी एक नए युग की शुरुआत है— जहाँ सीनियरिटी से ज़्यादा फिटनेस और पद से ज़्यादा उदाहरण मायने रखेगा।

सेना का यह निर्णय एक संदेश और संकल्प दोनों है। संदेश यह कि हर रैंक पर सैनिक वही है जो मैदान में सक्रिय रह सके और संकल्प यह कि सेना केवल युद्ध नहीं लड़ती, वह राष्ट्र को आत्मबल और अनुशासन की प्रेरणा भी देती है।

देखा जाये तो संयुक्त शारीरिक परीक्षण (CPT) भारतीय सेना को नयी पीढ़ी की फोर्स के रूप में गढ़ने का प्रयास है- जहाँ फिटनेस, तैयारी और नेतृत्व एक-दूसरे के पूरक हों। कुल मिलाकर देखें तो "फिटनेस अब केवल सैनिक की शर्त नहीं, बल्कि नेतृत्व की पहचान है।''

अभियान

व्रत के दिन सुई-धागा मत चलाओ — एक लोकविश्वास में छिपा ब्रह्म-तत्व

बहुत पुरानी बात है। गंगा किनारे बसे एक छोटे से नगर में सावित्री नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका जीवन साधारण था, पर हृदय में अपने पति के लिए गहरा प्रेम और श्रद्धा थी। वह हर वर्ष करवाचौथ का व्रत बड़े नियम और निष्ठा से करती थी। उस दिन वह न स्नान के बाद किसी से क्रोध करती, न किसी सांसारिक विषय में उलझती — केवल ईश्वर का नाम जपती और अपने पति के कल्याण की प्रार्थना करती।

एक वर्ष जब करवाचौथ का दिन आया, सावित्री प्रातःकाल उठी, स्नान किया, संकल्प लिया और पूजा की तैयारी में लग गई। उसके मन में शांति थी, आंगन में दीपक की लौ टिमटिमा रही थी, और उसके मन में भक्ति का संगीत बह रहा था। लेकिन तभी उसके छोटे पुत्र की धोती का किनारा फट गया। वह बालक रोने लगा कि "मां, आज सब बच्चे नये कपड़े पहने हैं, मैं कैसे जाऊं?" सावित्री का मन द्रवित हो गया। उसने सोचा — "क्या फर्क पड़ता है, बस दो टांके ही तो लगाने हैं।" और उसने सुई-धागा उठा लिया।

सुई जैसे ही उसके हाथ में आई, उसका मन एकदम स्थिरता से हटकर उस छोटे से छेद पर केंद्रित हो गया। उसकी प्रार्थनाओं की धारा वहीं ठिठक गई। उसने जल्दी-जल्दी टांका लगाया, पर तभी उसकी अंगुली में हल्की सी चुभन लगी और रक्त की एक बूंद निकली। उसी क्षण भीतर एक अजीब बेचैनी उठी — जैसे कोई सूक्ष्म चेतावनी हो। शाम तक जब चंद्रमा निकला और वह पूजा करने बैठी, तो उसके पति, जो यात्रा पर गए थे, अचानक रास्ते में घायल हो गए। बाद में जब वह लौटा, तो उसने कहा, "अजीब संयोग है, ठीक उसी समय मेरा हाथ घायल हुआ जब तुमने व्रत में सुई चुभोई होगी।" सावित्री के मन में गहरा पश्चाताप हुआ।

वह दिन उसके लिए एक शिक्षा बन गया। उसने समझा कि यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म सत्य है। व्रत के दिन मन, वचन और कर्म — तीनों को शुद्ध रखना आवश्यक है। सुई जैसे उपकरण केवल धातु नहीं होते, वे ऊर्जा को काटते हैं, जोड़ते हैं, या बदलते हैं। जब मन ईश्वर के प्रति स्थिर होता है, तब बाहरी नुकीले कार्य उस ऊर्जा प्रवाह को बाधित करते हैं। इसलिए दादी-नानी कहती थीं — "सुई मत चलाओ, यह दिन जोड़ने का नहीं, समर्पण का है।"

योगशास्त्र में कहा गया है कि उपवास के दिन मनुष्य की नाड़ियाँ अत्यंत सूक्ष्म हो जाती हैं। जब पेट खाली होता है और मन ईश्वर पर केंद्रित होता है, तब शरीर की विद्युत ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। उस समय यदि कोई नुकीली वस्तु त्वचा को छूती है, तो वह प्रवाह टूट जाता है, जैसे किसी शांत झील में पत्थर गिरा दिया जाए। सुई का चुभना केवल शारीरिक चोट नहीं, बल्कि उस सूक्ष्म एकाग्रता का विचलन है जो साधना के मूल में होती है।

लोक में इस विश्वास को एक सरल रूप में गढ़ दिया गया ताकि यह सबकी समझ में आ जाए। इसलिए दादी-नानी कहती थीं — "व्रत के दिन सुई मत चलाना, वरना पूजा का पुण्य घट जाएगा।" पर इसका भाव यह नहीं था कि ईश्वर सुई चलाने से रुष्ट हो जाएंगे, बल्कि यह था कि तुम्हारा मन भक्ति से हट जाएगा, साधना का प्रवाह टूट जाएगा।

करवाचौथ का व्रत केवल पति के दीर्घायु की कामना नहीं, बल्कि एक स्त्री की आत्मशक्ति की परख भी है। इस दिन वह अपनी इच्छाओं, भूख-प्यास और भौतिकता पर विजय प्राप्त करती है। जब उसका मन भक्ति में स्थिर होता है, तब वह देवी स्वरूपा बन जाती है। और देवी बनकर उसे किसी "सूक्ष्म" कार्य में उलझना शोभा नहीं देता, क्योंकि देवी कर्म नहीं करती — वह केवल आशीर्वाद देती है।

इसलिए कहा गया कि इस दिन सुई-धागे जैसे कर्म जो "बंधन" या "बंधन खोलने" के प्रतीक हैं, नहीं करने चाहिए। यह दिन उन कर्मों से ऊपर उठकर आत्मा को भगवान के प्रेम में डुबोने का है। यह वही क्षण है जब स्त्री अपनी साधना से अपने पति के जीवन में रक्षा कवच बुनती है — धागे से नहीं, बल्कि मन की शक्ति से। दादी-नानी के ये वचन पीढ़ियों का अनुभव हैं। वे भले ही विज्ञान की भाषा में न कह पाई हों, पर उनके अनुभव ने जीवन का विज्ञान सिखाया। "सुई मत चलाओ" में छिपा था — मन मत भटकाओ, ध्यान मत तोड़ो, अपने भीतर की ऊर्जा को अखंड रखो। यही सच्चा करवाचौथ का रहस्य है, यही स्त्री की तपशक्ति का मूल तत्व।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

प्रथम वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का समापन

दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में विभिन्न सेक्टर्स में 1212 एमओयू से भविष्य में उत्तर गुजरात में अनुमानित 3.24 लाख करोड़ रुपए का संभावित निवेश आने से क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई तथा उद्योग मंत्री श्री बलवंतसिंह राजपूत की प्रेरक उपस्थिति

▸▸ 'चार्टिंग अ पाथ टुवर्ड्ज विकसित गुजरात@2047' पुस्तक का अनावरण

▸▸ प्रतिष्ठित हथकरघा एवं हस्तकला अवॉर्ड तथा एमएसएमई वुमन अवॉर्ड प्रदान किए गए

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल -:

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को सरकार के साथ जोड़कर 'स्वच्छता से सेमीकंडक्टर' तक; हर क्षेत्र में विकास की ऊंचाइयां पार की हैं

▸▸ प्रधानमंत्री का लोगों की सहभागिता से हर गाँव-हर क्षेत्र में लोगों तक विकास पहुँचाने का विजन वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस से पूरा होगा

▸▸ प्रथम वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की सफलता का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री के सतत मार्गदर्शन, पार्टनर कंट्रीज के सहयोग, देश-विदेश के प्रतिनिधियों तथा टीम गुजरात के कर्मयोगियों को जाता है

▸▸ प्रथम रीजनल कॉन्फ्रेंस की सफलता 'वोकल फॉर लेकल' तथा 'गांव से ग्लोबल' की दिशा में अविरत आगे बढ़ना का विश्वास दृढ़ बनाती है

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को सरकार के साथ जोड़कर 'स्वच्छता से सेमीकंडक्टर' तक के हर क्षेत्र में विकास की ऊंचाइयां पार की हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के विकास केवल नगरों या बड़े शहरों तक सीमित न रहने और हर गाँव-हर क्षेत्र के लोगों को उसका सहभागी बनाने तथा विकास उन तक भी पहुंचाने के विजन से वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का राज्य में आयोजन हुआ है।

श्री पटेल मेहसाणा जिले के खेरवा स्थित गणपत विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित उत्तर गुजरात की दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) के शुक्रवार को हुए समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने 'वेल बिगन इज हाफ डन' उक्ति का उल्लेख करते हुए जोड़ा कि प्रधानमंत्री ने ग्लोबल विलेज तथा वोकल फॉर लोकल का जो विचार दिया, उसे प्रथम रीजनल कॉन्फ्रेंस की सफलता ने बल दिया है। मुख्यमंत्री ने उत्तर गुजरात की इस वीजीआरसी की फलश्रुति का वर्णन करते हुए कहा कि दो दिनों में 21 क्षेत्रों में निवेश के लिए 1212 एमओयू हुए। इनके द्वारा उत्तर गुजरात में आगामी समय में अनुमानित 3.24 लाख करोड़ रुपए का संभावित निवेश आएगा और इस क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

उन्होंने इस वीजीआरसी की ऐसी अप्रतिम सफलता का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सतत मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने पार्टनर कंट्रीज, कॉन्फ्रेंस में जुड़े देश-विदेश के प्रतिनिधियों, केन्द्र सरकार के मंत्रियों तथा टीम गुजरात के कर्मयोगियों को भी इस सफलता का हकदार बताया। श्री भूपेंद्र पटेल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के दिशादर्शन में अब तक 10 वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सफलतापूर्वक आयोजित की गई और हर समिट में हमें नई ऊर्जा, रोजगार के नए अवसर तथा नए निवेश मिले हैं। अब क्षेत्रीय वाइब्रेंट कॉन्फ्रेंस का प्रयोग और विस्तृत एवं प्रासंगिक बना है। उत्तर गुजरात की इस प्रथम रीजनल कॉन्फ्रेंस की सफलता दर्शाती है कि राज्य में विकास 'गांव से ग्लोबल' की दिशा में अविरत आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2003 में वाइब्रेंट समिट के विचार को तत्कालीन समय में चुनौतियों के बीच साकार कर वाइब्रेंट समिट को उत्तरोत्तर उपलब्धियाँ दिलाए जाने का विस्तार से विश्लेषण किया।

उन्होंने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में आयोजित चर्चा सत्रों, प्रेजेंटेशन्स तथा एमओयू रीजनल डेवलपमेंट का नया अध्याय रचेंगे। उन्होंने आगामी समय में आयोजित होने वाली अन्य अंचलों की रीजनल कॉन्फ्रेंस में लोगों की सक्रियता की अपेक्षा व्यक्त की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2003 में वाइब्रेंट समिट का आयोजन कर जो दीर्घदृष्टि दिखाई थी, वह अब फलीभूत हुई है। उनके इस मॉडल से प्रेरित होकर आज देश के अन्य राज्य भी ऐसे इवेंट का आयोजन कर रहे हैं। कोरोना काल की चुनौतियों के बावजूद वाइब्रेंट की यात्रा अविरत जारी रही है। अब, गुजरात के चार क्षेत्रों में से एक उत्तर गुजरात से रीजनल वाइब्रेंट की शुरुआत हुई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर गुजरात पूरे राज्य का श्रेष्ठ रीजन बनकर उभरेगा।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री बलवंतसिंह राजपूत ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत राज्य के प्रत्येक क्षेत्र को विकास में सहभागी बनाने के उम्दा उद्देश्य के साथ की गई है। इस पहले संस्करण में दो दिनों तक लघु, मध्यम और मेगा उद्योगों तथा हितधारकों के साथ गुणवत्ता और कौशल विकास जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई और समझौता ज्ञापनों (एमओयू) किए गए हैं।

श्री राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के छोटे से छोटे व्यक्ति की चिंता करते हैं। युद्ध, टैरिफ (टैक्स) और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के समय में भी जीएसटी सुधारों और 12 लाख रुपए तक की आय पर आयकर छूट देने जैसे निर्णयों के माध्यम से वे 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए देश को प्रोत्साहित कर रहे हैं। गुजरात में भी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मजबूत नेतृत्व में सिंगल विंडो सिस्टम और उद्योग-उन्मुख नीतियों के परिणामस्वरूप राज्य में कारोबार सुगमता के श्रेष्ठ वातावरण का निर्माण हुआ है। उद्योग और खान विभाग की प्रधान सचिव सुश्री ममता वर्मा ने कहा कि रीजनल वाइब्रेंट समिट राज्य के समान और संतुलित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कॉन्फ्रेंस से क्षेत्रीय स्तर पर उद्योगों के बीच परस्पर भागीदारी, नेटवर्किंग और विचारों का आदान-प्रदान संभव हुआ है, जिससे उद्योग और रोजगार के नए क्षेत्रों को उभरने का अवसर मिलेगा। उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप ने दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस की सफलता का वर्णन करते हुए कहा कि इस समिट में 34 विदेशी कंपनियों ने हिस्सा लिया है। 170 से अधिक स्टार्टअप्स भी शामिल हुए हैं। छोटे-बड़े सभी उद्योगपति इसमें सहभागी बने हैं। 80 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ यह समिट वैश्विक बन गई है। कृषि सेमिनार में जापान, वियतनाम, दक्षिण कोरिया और नीदरलैंड जैसे देशों ने हिस्सा लिया। देश और दुनिया से कुल 29,000 रजिस्ट्रेशन हुए, जिनमें 440 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए। महेन्द्रा एग्री के सीईओ श्री अशोक शर्मा और वेलस्पन समूह की सहायक कंपनी वेलस्पन न्यू एनर्जी लिमिटेड के सीईओ श्री कपिल माहेश्वरी ने रीजनल वाइब्रेंट कॉन्फ्रेंस के आयोजन की सराहना करते हुए गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के इकोसिस्टम की प्रशंसा की। उन्होंने, विशेषकर आलू खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में गुजरात की प्रगति को लेकर अपने सकारात्मक विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी, अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती अंजू शर्मा, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस.जे. हैदर, गणपत विश्वविद्यालय के संस्थापक श्री गणपत पटेल, महिन्द्रा के सीईओ श्री देवेन्द्र सिंह सहित उद्योग जगत के कई अग्रणी, शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि और औद्योगिक एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

कर्मचारी हित निधि (SBF) - भावनगर मंडल के द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम – 2025 का आयोजन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल पर कर्मचारी हित निधि (Staff Benefit Fund - SBF) के तत्वावधान में "महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम – 2025" के अंतर्गत "Financial Discipline and Wealth Habits for Women" विषय पर एक ऑफ़लाइन सेमिनार का सफल आयोजन किया गया।

यह सेमिनार दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 को सांय 16.00 बजे मंडल कार्यालय सभागृह, भावनगर परा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी एवं अध्यक्ष, कर्मचारी हित निधि समिति श्री हुबलाल जगन की अध्यक्षता में किया गया।

कार्यक्रम में Advisor Skill Development Organisation के प्रशिक्षक श्री देवदत्त आर. पाठक ने महिला रेलकर्मियों एवं अधिकारियों को "वित्तीय अनुशासन और धन संबंधी आदतें" विषय पर उपयोगी मार्गदर्शन एवं प्रेरणा प्रदान की। उन्होंने आर्थिक योजना, निवेश की समझ एवं वित्तीय स्वतंत्रता के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम महिला कर्मचारियों में वित्तीय साक्षरता एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

इस अवसर पर सहायक कार्मिक अधिकारी श्री राधेश्याम जी के मार्गदर्शन में कल्याण शाखा की टीम द्वारा कार्यक्रम का सुंदर एवं सुव्यवस्थित आयोजन किया गया। महिला कर्मचारियों ने इस सेमिनार में सक्रिय भागीदारी करते हुए इसे अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक बताया।

पश्चिम रेलवे द्वारा त्योहारी सीज़न 2025 के दौरान व्यापक भीड़ प्रबंधन व्यवस्था

यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र सुरक्षित और व्यवस्थित त्योहारी यात्रा सुनिश्चित करने हेतु पश्चिम रेलवे की सक्रिय तैयारी

(जीएनएस)। त्योहारी सीज़न के दौरान यात्रियों के सुरक्षित और व्यवस्थित बोर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए समर्पित होल्डिंग एरिया आगामी त्योहारों के दौरान होने वाली भीड़ और यात्रियों की आवाजाही में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा सुरक्षित, सुचारू और कुशल रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक भीड़ प्रबंधन और यात्री सुविधा उपाय शुरू किए गए हैं। मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस, बोरीवली, वापी, वलसाड, उधना और सूरत सहित प्रमुख स्टेशनों पर विशेष व्यवस्थाएँ की गई हैं।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सभी निर्दिष्ट यात्री आवास क्षेत्रों में बैठने की व्यवस्था, पेयजल सुविधा, शौचालय, पर्याप्त रोशनी, पंखे और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली जैसी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। यात्रियों के प्रवेश और टिकटिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रत्येक स्थान पर अतिरिक्त काउंटर स्थापित किए गए हैं, साथ ही कतार नियमन, सहायता और सुरक्षा के लिए प्रत्येक स्टेशन पर लगभग 20 अतिरिक्त टिकट चेकिंग स्टाफ और आरपीएफ कर्मियों की तैनाती भी की गई है।

श्री विनीत ने आगे बताया कि ट्रेन प्रस्थान से पहले प्रतीक्षारत यात्रियों को आराम से समायोजित करने के लिए सभी प्रमुख स्टेशनों पर पर्याप्त कवर्ड होल्डिंग क्षमता बनाई गई है। बांद्रा टर्मिनस पर, प्लेटफ़ॉर्म संख्या 1 के पूर्व की ओर प्रवेश द्वार के पास 210 वर्ग मीटर से अधिक का आश्रय क्षेत्र उपलब्ध कराया गया है, जबकि वापी में, यात्रियों के एकत्र होने के लिए एफओबी लैंडिंग के पास 110 वर्ग मीटर से अधिक का कवर्ड क्षेत्र तैयार किया गया है। उधना स्टेशन को पूरे मंडल में सबसे बड़ी होल्डिंग क्षमता प्रदान की गई है, जिसमें स्टेशन के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर 3200 वर्ग मीटर से अधिक के तीन चिह्नित कवर्ड स्थान हैं, जिनमें से एक क्षेत्र वर्तमान में होल्डिंग क्षमता को और बढ़ाने के लिए निर्माणाधीन है। इसी प्रकार, सूरत में, 1,200 वर्ग मीटर से अधिक के दो निर्दिष्ट होल्डिंग क्षेत्र तैयार किए गए हैं, एक पीआरएस कार्यालय से सटे पश्चिमी प्रवेश द्वार के पास और दूसरा बुकिंग कार्यालय के पास पूर्व की ओर जिससे त्योहारों के समय होने वाली भीड़ के दौरान व्यवस्थित रूप से यात्रियों को लाने और नियमित रूप से चढ़ने में मदद मिलेगी। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों से अपील की गई है कि वे प्लेटफॉर्म या प्रवेश द्वारों के पास भीड़ लगाने के बजाय निर्धारित प्रतीक्षालयों का उपयोग करें, ताकि व्यस्त समय के दौरान आवाजाही सुचारू रूप से नियंत्रित की जा सके। यात्रियों से ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों के दिशानिर्देशों का पालन करने का भी आग्रह किया गया है, क्योंकि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य सभी यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देना है। त्योहारों की भीड़ के दौरान कम समय में हजारों यात्रियों के ट्रेनों में चढ़ने की उम्मीद के साथ व्यवस्था बनाए रखने और समय पर प्रस्थान सुनिश्चित करने में सामूहिक सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सत्यमेव जयते
गुजरात सरकार

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

विकास सप्ताह
२४ वर्ष जनविश्वास, सेवा अने समर्पणनां

हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी

माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल
के नेतृत्व में
विकास सप्ताह -2025 अंतर्गत

विकसित गाँव
विकसित गुजरात

दिनांक: 11 अक्टूबर 2025 | दिन: शनिवार | समय: सुबह 9:30 बजे
स्थान: योगी सभा गृह, स्वामिनारायण मंदिर, कालावाड रोड, राजकोट

- **उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ग्राम पंचायतों और सरकारी संस्थाओं का सम्मान।**
- **लगभग ₹194 करोड़ की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए शिलान्यास समारोह।**
- राजकोट जिला: मार्ग और मकान विभाग: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास कार्यों का शिलान्यास।
- राजकोट महानगरपालिका: शहरी क्षेत्र के विकास कार्यों का शिलान्यास।
- उपलेटा नगरपालिका: नगरपालिका क्षेत्र के विकास कार्यों का शिलान्यास।
- **प्रदर्शनी**
  प्लास्टिक से बनी अनूठी वस्तुएं, पटोला-हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, हस्तकला और मोती काम सहित विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन।
- **ड्रोन दीदी**
  न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से कौशल और दक्षता का प्रदर्शन

वोकल फॉर लोकल

हर घर स्वदेशी,
घर-घर स्वदेशी

पंचायत, ग्राम गृह निर्माण एवं ग्राम विकास विभाग, गुजरात सरकार

सीधा प्रसारण : CMOGuj CMOGuj CMOGujarat CMOGujarat

मेहसाणा में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस-उत्तर गुजरात के दूसरे दिन क्षेत्रीय एमएसएमई कॉन्क्लेव आयोजित

यदि एमएसएमई समृद्ध होंगे तो गुजरात समृद्ध होगा और गुजरात समृद्ध होगा तो विकसित भारत का विजन भी साकार होगा
-श्री संदीप सागले (आईएएस), आयुक्त, एमएसएमई

कॉन्क्लेव के दौरान 'क्लस्टरों से प्रतिस्पर्धात्मकता तक : वैश्विक व्यापार के लिए एमएसएमई को सक्षम बनाना' विषय पर पैनल चर्चा आयोजित हुई

(जीएनएस)। गांधीनग : मेहसाणा में चल रही दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी)-उत्तर गुजरात के दूसरे दिन यानी शुक्रवार, 10 अक्टूबर को क्षेत्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) कॉन्क्लेव आयोजित हुई। इस कॉन्क्लेव की मुख्य थीम 'उद्यम उत्कर्षः मजबूत एमएसएमई, सशक्त भारत' थी।

गुजरात सरकार के एमएसएमई आयुक्त श्री संदीप सागले (आईएएस) ने क्षेत्रीय एमएसएमई कॉन्क्लेव की शुरुआत की। उन्होंने कॉन्क्लेव की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। श्री सागले ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दो दशक पहले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की संकल्पना की थी और वर्ष 2003 में इस समिट की शुरुआत के साथ यह संकल्पना साकार हुई थी। आज इस समिट के फायदों को गुजरात के क्षेत्रीय स्तरों तक पहुंचाने के लिए पूरे गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जो 'विकसित भारत@2047' के विजन को मूर्त रूप देगा।

गुजरात के एमएसएमई सेक्टर की चर्चा करते हुए श्री संदीप सागले ने कहा कि गुजरात के एमएसएमई कठोर परिश्रम और लचीलेपन का प्रतीक हैं। ये एमएसएमई लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, गुजरात के औद्योगिक आउटपुट और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान देते हैं और इसके जरिए भारत की जीडीपी में भी योगदान देते हैं।

उन्होंने कहा कि आज, जब हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब हमें इस बात पर फोकस करना होगा कि अनिश्चितता से भरी इस दुनिया में हमारे एमएसएमई न केवल अपना अस्तित्व बचाए रखें, बल्कि विकास करने के साथ-साथ समृद्ध भी हों। उन्होंने एमएसएमई को मजबूत करने के लिए कस्टमर फोकस (ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना), ग्लोबल इंटीग्रेशन (वैश्विक एकीकरण), डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन (डिजिटल बदलाव) और रेजिलिएन्स एवं इनोवेशन (लचीलापन एवं नवाचार) सहित कुल चार मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही।

उन्होंने अपनी चर्चा का समापन करते हुए कहा कि गुजरात ने हमेशा भारत के औद्योगिक विकास का नेतृत्व किया है, और वह भी केवल अपने कद के आधार पर नहीं, बल्कि पूरी स्पिरिट यानी उत्साह और भाव के साथ। हमारे एमएसएमई इसी स्पिरिट को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें अपने एमएसएमई को मजबूत करना होगा, क्योंकि अगर एमएसएमई समृद्ध होंगे तो गुजरात समृद्ध होगा और गुजरात समृद्ध होगा तो विकसित भारत का विजन भी साकार होगा।

इसके बाद, वाधवाणी फाउंडेशन के संस्थापक श्री मितुल पटेल ने 'गुजरात के एमएसएमई की विकास क्षमताओं को उजागर करना' (अलॉकिंग द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ गुजरात्स एमएसएमईस) विषय पर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि वाधवाणी फाउंडेशन का विजन विकसित भारत के अनुरूप है। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में एमएसएमई के महत्व के साथ ही इस बारे में भी अपना विजन प्रस्तुत किया कि कैसे ये एमएसएमई गुजरात और भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करेंगे। इसके अलावा, उन्होंने उत्तर गुजरात के

वर्चुअल बिजनेस ग्रोथ एक्सेलरेटर के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए।

तत्पश्चात, 'क्लस्टरों से प्रतिस्पर्धात्मकता तक : वैश्विक व्यापार के लिए एमएसएमई को सक्षम बनाना' (फ्रॉम क्लस्टर्स टू कॉम्पिटिटिवनेस : इनेबलिंग एमएसएमईस फॉर ग्लोबल ट्रेड) विषय पर पैनल चर्चा का आयोजन हुआ। पैनल चर्चाओं में छोटे उद्योगों को निर्यात विविधीकरण, मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी ढंग से उपयोग, टैरिफ (टैक्स) व्यवस्थाओं की जानकारी और व्यापार अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए लचीलेपन के विकास के माध्यम से वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत होने के लिए मार्गदर्शन दिया गया।

पैनल चर्चा में भारत में रूस की जीआर और फाइनेंस सेक्टर तथा व्यापार प्रतिनिधित्व की प्रमुख सुश्री ज्लाटा अंतुशेवा, दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डीआईसीसीआई) के संस्थापक सह चेयरमैन डॉ. मिलंद कांबले, इंडिया एक्जिम फिनसर्व की प्रबंध निदेशक और सीईओ सुश्री हिरवा ममतोरा, मंत्र एग्री सोल्यूशन प्रा.लि. के सीईओ श्री जयदीप भाटिया, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान के महानिदेशक डॉ. आशुतोष मुरकुटे और Sberbank इंडिया के निदेशक श्री शंखो गुप्ता ने भाग लिया। पैनल चर्चा में मॉडरेटर की भूमिका विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के संयुक्त महानिदेशक डॉ. राहुल सिंह ने निभाई।

इस पैनल चर्चा में नियामक ढांचे को समझकर सप्लाई चैन की चुनौतियों को संबोधित करते हुए टैरिफ और नीतिगत बदलावों के सामने लचीलापन विकसित करते हुए और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता एवं स्थिरता मानदंडों के साथ संरेखित करते हुए एमएसएमई को उनके वैश्विक फुटप्रिंट का विस्तार करने के लिए ज्ञान और रणनीति से लैस करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस पैनल चर्चा ने एमएसएमई के लिए बाजार सुलभता, निर्यात विविधीकरण और वैश्विक संबंधों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान की, जो एमएसएमई को क्लस्टरों से आगे बढ़ने, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता प्रदान करने और 2047 के विकसित भारत के विजन में योगदान देने के लिए सक्षम बनाएगी।

कार्यक्रम के अंत में दक्षिण रेलवे के श्री विहार ठाकर, ओएनजीसी-मेहसाणा के श्री रवि जैन, मारुति सुजुकी-गुजरात प्लांट के श्री मंदार गाडगिल और टाटा अग्रतास के श्री आनंद सोडा द्वारा वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य उद्योग संबंधों को मजबूत बनाना और स्थानीय उद्योग विकास को बढ़ावा देना है।

उल्लेखनीय है कि दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी)-उत्तर गुजरात का आयोजन 'हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी' मंत्र के साथ मेहसाणा स्थित गणपत विश्वविद्यालय में 9 और 10 अक्टूबर, 2025 को किया गया है। यह पूरे गुजरात में आयोजित होने वाली चार वीजीआरसी की श्रृंखला की पहली कॉन्फ्रेंस है, जिसका उद्घाटन कल यानी गुरुवार को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने किया था। यह रीजनल कॉन्फ्रेंस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की सफलता और विरासत के आधार पर आयोजित की गई है। यह कॉन्फ्रेंस राज्य की क्षेत्रीय क्षमताओं को प्रदर्शित करेगी, जमीनी स्तर के विकास का उपयोग करेगी और 'विकसित भारत@2047' और 'विकसित गुजरात@2047' के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप होगी।

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस-उत्तर

वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई की अध्यक्षता में उत्तर गुजरात के आर्थिक क्षेत्र के लिए तैयार किए गए आर्थिक मास्टर प्लान पर सेमिनार आयोजित

उत्तर गुजरात में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, नए निवेशक आएंगे और लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा : वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई

(जीएनएस)। गांधीनगर, : उत्तर गुजरात के मेहसाणा के खेरवा गांव में स्थित गणपत विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) के दूसरे दिन, शुक्रवार को राज्य के वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई की अध्यक्षता में उत्तर गुजरात के आर्थिक क्षेत्र के लिए तैयार किए गए आर्थिक मास्टर प्लान पर सेमिनार और पैनल चर्चा का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने कहा कि यह मास्टर प्लान गुजरात के 33 जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार को मौजूदा 280 बिलियन डॉलर (वित्तीय वर्ष 2023) से बढ़ाकर 3.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक तक पहुंचाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने का रोडमैप है।

उन्होंने आगे कहा कि इस मास्टर प्लान के अंतर्गत उत्तर गुजरात में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, नए निवेशक आएंगे और लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित बनाने के स्वप्न को साकारक करने में यह मास्टर प्लान काफी उपयोगी सिद्ध होगा।

गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (ग्रिट) की एजीक्यूटिव कमेटी की चेयरमैन सह सीईओ श्रीमती एस. अपर्णा ने कहा कि गुजरात के ऐतिहासिक और आर्थिक दृष्टिकोण से छह महत्वपूर्ण एवं मुख्य आर्थिक क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इन क्षेत्रों में उत्तर गुजरात, कच्छ, मध्य गुजरात, सौराष्ट्र, तटीय सौराष्ट्र और सूरत शामिल हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने वीजीआरसी के पहले दिन यानी गुरुवार को राज्य के छह मुख्य आर्थिक क्षेत्रों के लिए तैयार किए गए क्षेत्रीय आर्थिक मास्टर प्लान (रीजनल इकोनॉमिक मास्टर प्लान) का अनावरण किया था।

उत्तर गुजरात के आर्थिक विकास के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, अरवल्ली और गांधीनगर को कवर करते हुए तैयार किए गए इस मास्टर प्लान में 23 से 24 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित पूंजी निवेश किया जाएगा। इस निवेश के अंतर्गत सवा पांच लाख करोड़ रुपए का निवेश राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा, जबकि अन्य पूंजी निवेश निजी कंपनियां, संस्थानों और इंडस्ट्रीज से लाया जाएगा। इस प्लान के माध्यम से उत्तर गुजरात में 12 मिलियन नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

इस प्रकार, इस प्लान के जरिए उत्तर गुजरात की आर्थिक प्रगति को एक नई गति मिलेगी। इसके अलावा, पूंजी निवेश के अनेक अवसर प्राप्त होंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इस अवसर पर नीति आयोग की प्रमुख आर्थिक सलाहकार श्रीमती अन्ना रॉय ने उत्तर गुजरात के आर्थिक विकास को लेकर तैयार किए गए मास्टर प्लान की सराहना की और राज्य सरकार एवं ग्रिट के कार्यों की प्रशंसा कर उन्हें बधाई भी दी।

इस अवसर पर सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव (योजना) श्रीमती आर्द्रा अग्रवाल और ग्रिट की श्रीमती श्रुति चरण और उद्योगपतियों सहित कई निवेशक मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि आर्थिक वृद्धि का लाभ युवाओं को मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में उद्योगों के सहयोग से रीजनल स्किलिंग सेंटर्स और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (ग्रीन स्किल्स, ब्लू इकोनॉमी, लॉजिस्टिक्स और एआई एकेडमी आदि) स्थापित किए जाएंगे। इन योजनाओं और आर्थिक गतिविधियों से राज्य के युवाओं के लिए लगभग 280 लाख नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस प्रकार, ये क्षेत्रीय मास्टर प्लान हरेक क्षेत्र की स्थानीय उत्पादन क्षमताओं के अनुरूप फ्यूचरिस्टिक सेक्टर को लक्ष्य बनाएंगे।

अहमदाबाद स्टेशन पुनर्विकास के अंतर्गत 100 वर्ष पुराने सारंगपुर रोड ओवर ब्रिज का पुनर्निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर

(जीएनएस)। सारंगपुर रोड ओवर ब्रिज पुनर्निर्माण से यातायात होगा और अधिक सुगम पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है पुनर्विकास कार्य के अंतर्गत सारंगपुर रोड ओवर ब्रिज (ROB) का पुनर्निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। यह पुल अहमदाबाद (कालूपुर) स्टेशन के दक्षिण दिशा में स्थित है और अंबेडकर चौक के पश्चिम दिशा में तथा रखियाल रोड को पूर्व दिशा में जोड़ता है। लगभग 100 वर्ष पुराने इस पुल के पुनर्निर्माण का कार्य जनवरी 2025 में रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) को सौंपा गया था। पुनर्निर्माण के बाद रेलवे हिस्से में लेन की संख्या बढ़ाकर छह कर दी जाएगी, जिससे वाहनों की आवाजाही में सुगमता आएगी और यातायात जाम में उल्लेखनीय कमी होगी। यह पुल अहमदाबाद स्टेशन के आगामी एलिवेटेड रोड नेटवर्क से भी जुड़ेगा, जिससे

यात्रियों और आम नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त होगी।

पुल की कुल लंबाई दो हिस्सों में विभाजित है — एप्रोच की लंबाई 497 मीटर और रेलवे स्पैन की लंबाई 138 मीटर है, जिसमें 107 मीटर का सिंगल स्पैन बो-स्ट्रिंग गर्डर ब्रिज शामिल है। पुराने एप्रोच और रेलवे स्पैन को हटाने का कार्य पूरा हो चुका है। यह कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण था, जिसे रेलवे संचालन को प्रभावित किए बिना ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

वर्तमान में कार्य तेजी से प्रगति पर है — 132 पाइलिंग कार्य पूरे हो चुके हैं, 23 में से 18 पिलर तैयार हैं तथा 76 में से 44 गर्डर ढाले जा चुके हैं। पूरे प्रोजेक्ट का कार्य अगस्त 2026 तक पूरा होने की संभावना है। इस पुल के निर्माण से अहमदाबाद स्टेशन क्षेत्र में यातायात व्यवस्था अधिक आधुनिक, सुरक्षित और सुगम बनेगी। यात्रियों, स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों को निर्बाध और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। RLDA इस महत्वपूर्ण परियोजना को निर्धारित 18 माह की अवधि में पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, जिससे अहमदाबाद शहर में बेहतर शहरी कनेक्टिविटी और सुगम आवागमन सुनिश्चित हो सकेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'राष्ट्र प्रथम' भाव को उजागर करने वाली अनूठी प्रस्तुति 'मेरा देश पहले' गुजरात में सर्वप्रथम गिफ्ट सिटी में आयोजित हुई

मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों, सामाजिक जीवन के अग्रणियों, वरिष्ठ उद्योगकारों तथा बड़ी संख्या में नागरिकों ने इस मंचन को देखा

गांधीनगर, 10 अक्टूबर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आकार ले रहे नए भारत के रूपांतरण की एक अनूठी कहानी 'मेरा देश पहले' का गुजरात में सर्वप्रथम शो 10 अक्टूबर शुक्रवार को गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में आयोजित हुआ।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों, सामाजिक जीवन के अग्रणियों, वरिष्ठ उद्योगकारों तथा बड़ी संख्या में नागरिकों ने इस मंचन को देखा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सदैव राष्ट्रहित सर्वोपरि रखकर अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है। उनके समग्र जीवन की अनेक घटनाएँ-प्रसंग देशवासियों में देशप्रेम, समर्पण तथा 'राष्ट्र प्रथम' के भाव के लिए प्रेरणादायी बने हैं। 'मेरा देश पहले' श्री नरेन्द्र मोदी की उस अद्वितीय यात्रा को मेगा शो द्वारा जीवंत करता है।

'मेरा देश पहले' देश के अन्य राज्यों में सफल तथा प्रशंसनीय मंचन के बाद गुजरात में पहली बार गिफ्ट सिटी परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें निःशुल्क प्रवेश रखा गया था। प्रसिद्ध सर्जक श्री मनोज मुंतशिर निर्मित 'मेरा देश पहले' का मंचन निहारने के लिए आमंत्रित सहित ऑनलाइन पंजीकरण से प्रवेश प्राप्त करने वाले नागरिक पहुँचे और उन्होंने इस प्रस्तुति को देखा।

केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने गुजरात के पहले ग्रीन रेलवे स्टेशन – एकतानगर का किया दौरा

(जीएनएस)। केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने दिनांक 09 अक्टूबर 2025 को भारत के सबसे सुंदर और आधुनिक रेलवे स्टेशनों में से एक तथा गुजरात के पहले "ग्रीन रेलवे स्टेशन" एकता नगर का दौरा किया।

श्री सोमन्ना ने रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण कर स्वच्छता, आधुनिक सुविधाओं एवं ग्रीन टेक्नोलॉजी से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

मीडिया को संबोधित करते हुए श्री सोमन्ना ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में भारतीय रेल ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साकार करते हुए उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2025- 26 में गुजरात को 17,155 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है, जो वर्ष 2009 -14 के आवंटन के मुकाबले 29 गुना है। वर्ष 2014 से अभी तक गुजरात में 2739 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया तथा 3,144 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को विद्युतीकृत किया गया है। गुजरात राज्य में 87 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशनों के रूप में विकसित किया जा रहा है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करते हुए गुजरात में विभिन्न स्टेशनों पर 97 लिफ्टों और 50 एस्कलेटरों का निर्माण किया गया है, साथ

ही 335 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस समय गुजरात राज्य में चार वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन हो रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एकता नगर, वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत और राजकोट जैसे शहरों में रेलवे सुविधाओं को आधुनिक स्तर तक पहुँचाया गया है। प्रधानमंत्री के "विकसित भारत 2047" के विजन में रेलवे की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

एकतानगर स्टेशन पर निरीक्षण से पहले माननीय रेल राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना जी ने आज वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के साथ सूरत-एकता नगर खंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने रेल पटरियों की सुरक्षा और परिचालन दक्षता की समीक्षा की। साथ ही उन्हें ट्रैक सेफ्टी एवं परिचालन दक्षता के साथ चल रही विकास परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई ।

गुजरात के नागरिकों की परिवहन सेवा में हुई वृद्धि

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने नागरिकों की सेवा में 201 नई एसटी बसों को हरी झंडी दिखाकर गांधीनगर से रवाना किया

परिवहन राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी की प्रेरक उपस्थिति
- नई बसों में 136 सुपर एक्सप्रेस, 60 सेमी लग्जरी और 5 मीडी बसें शामिल
- दिवाली के त्योहार में सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 4200 अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू
- एसटी निगम प्रतिदिन 8000 से अधिक बसों के संचालन के जरिए 27 लाख से अधिक यात्रियों को यातायात सेवाएं प्रदान करता है

गांधीनगर, 10 अक्टूबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के प्रत्येक नागरिक को उच्च गुणवत्ता युक्त, समयबद्ध और सुरक्षित परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग का नई टेक्नोलॉजी के साथ बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और बसों का आधुनिकीकरण करने के लिए लगातार मार्गदर्शन किया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और परिवहन राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी ने नागरिकों के लिए बस सेवाओं को और अधिक सुविधा युक्त बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को गांधीनगर से गुजरात राज्य परिवहन निगम (एसटी निगम) की 201 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न रूटों के लिए रवाना किया। इन बसों में 136 सुपर एक्सप्रेस, 60 सेमी लग्जरी और 5 मिडी बसें शामिल हैं। गांधीनगर में आयोजित बसों के लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री

और परिवहन राज्य मंत्री ने बसों का औपचारिक रूप से लोकार्पण कर बसों के ड्राइवर और कंडक्टरों को बधाई दी और उनका अभिवादन स्वीकार किया।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने दिवाली के अवसर पर 4200 अतिरिक्त बसों के संचालन का भी शुभारंभ किया ताकि राज्य का प्रत्येक नागरिक अपने परिवार के साथ त्योहार मना सके।

हाल ही में गुजरात एसटी निगम की ओर से भाद्रपद पूर्णिमा के दौरान अंबाजी के मेले के लिए 28,000 से अधिक, पावागढ़ शारदीय नवरात्रि के लिए 22,000 से अधिक और जन्माष्टमी के त्योहारों के दौरान 7000 से अधिक फेरों का संचालन कर नागरिकों को उत्तम परिवहन सेवा का परिचय दिया था।

उल्लेखनीय है कि गुजरात एसटी निगम प्रतिदिन 8000 से अधिक बसों के माध्यम से 33 लाख किलोमीटर का संचालन कर राज्य के 27 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाता है।

लोकार्पण समारोह में गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिल्पीबेन पटेल, गांधीनगर उत्तर की विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल, गांधीनगर दक्षिण के विधायक श्री अल्पेशभाई ठाकोर और माणसा के विधायक श्री जयंतीभाई पटेल के अलावा परिवहन विभाग और एसटी निगम के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

पठानकोट-जम्मू तवी सेक्शन लैंड स्लाइडिंग के चलते अवरोध के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी

उत्तर रेलवे के कठुआ-माधोपुर पंजाब में डाउन लाइन पर ब्रिज संख्या 17 पर मिसअलाइमेंट होने एवं पठानकोट-जम्मू तवी सेक्शन में लैंड स्लाइडिंग के चलते अवरोध के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी।जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

पूर्णतः रद्द ट्रेनें

- 11 अक्टूबर 2025 की गाडी संख्या 19027, बांन्द्रा टर्मिनस-जम्मूतवी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- 13 अक्टूबर 2025 की गाडी संख्या 19028, जम्मूतवी-बांन्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- 12 अक्टूबर 2025 की गाडी संख्या 19415, साबरमती-श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- 14 अक्टूबर 2025 की गाडी संख्या 19416, श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा-साबरमती एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- गाडी संख्या 19107, भावनगर टर्मिनस-एमसीटीएम उधमपुर एक्सप्रेस अगली सूचना तक रद्द रहेगी।
- गाडी संख्या 19108, एमसीटीएम उधमपुर-भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस अगली सूचना तक रद्द रहेगी।

आंशिक रद्द ट्रेने

- गाडी संख्या 19027, बांन्द्रा टर्मिनस-जम्मूतवी एक्सप्रेस 18 अक्टूबर 2025 से अगली सूचना तक लुधियाना स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा यह ट्रेन लुधियाना-जम्मूतवी के बीच आंशिक रद्द रहेगी।
- गाडी संख्या 19028, जम्मूतवी-बांन्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 20 अक्टूबर 2025 से अगली सूचना तक जम्मूतवी के स्थान पर लुधियाना से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा यह ट्रेन जम्मूतवी-लुधियाना के बीच आंशिक रद्द रहेगी।
- गाडी संख्या 19415, साबरमती-श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा 19 अक्टूबर 2025 से अगली सूचना तक अमृतसर स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा यह ट्रेन अमृतसर-श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा के बीच आंशिक रद्द रहेगी।
- गाडी संख्या 19416, श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा-साबरमती एक्सप्रेस 21 अक्टूबर 2025 से अगली सूचना तक श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा के स्थान पर अमृतसर से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा यह ट्रेन श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा-अमृतसर के बीच आंशिक रद्द रहेगी।
- गाडी संख्या 19223, साबरमती-जम्मूतवी 15 अक्टूबर 2025 तक फिरोजपुर केंट स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा यह ट्रेन फिरोजपुर केंट-जम्मूतवी के बीच आंशिक रद्द रहेगी।
- गाडी संख्या 19224, जम्मूतवी-साबरमती एक्सप्रेस 15 अक्टूबर 2025 तक जम्मूतवी के स्थान पर फिरोजपुर केंट से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा यह ट्रेन जम्मूतवी-फिरोजपुर के बीच आंशिक रद्द रहेगी।

ट्रेन के ठहराव, संरचना एवं समय-सारणी संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया भारतीय रेल की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन करें।

स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत पश्चिम रेलवे द्वारा स्वच्छ परिवेश और खाद्य स्वच्छता पर विशेष ध्यान

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, कारखानों और ट्रेनों में स्वच्छता, सफाई और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 1 से 15 अक्टूबर, 2025 तक स्वच्छता पखवाड़ा 2025 मना रही है। इस अभियान के शुभारंभ और प्रारंभिक गतिविधियों के आधार पर 8वें और 9वें दिन स्वच्छ परिसर और स्वच्छ आहार पर केंद्रित पहलों के साथ अभियान आगे बढ़ा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आठवें दिन 8 अक्टूबर, 2025 को रेलवे कार्यालयों, कॉलोनियों, विश्राम/प्रतीक्षा कक्षों, विश्राम गृहों और शयनगृहों में स्वच्छता में सुधार हेतु सघन स्वच्छता/फ्यूमिगेशन अभियान चलाए गए। यात्रियों और रेलवे कॉलोनियों के निवासियों के लिए सूखे और गीले कचरे को अलग-

अलग करने के बारे में 70 से अधिक जागरूकता अभियान आयोजित किए गए। रेलवे कॉलोनियों में कचरा सफाई के लिए जनभागीदारी अभियान चलाया गया जिसमें 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 50 स्टेशनों/कॉलोनियों में वृक्षारोपण और भूनिर्माण गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

नौवें दिन, स्वच्छ आहार पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें खाद्य स्वच्छता, विक्रेता स्वच्छता और उचित अपशिष्ट निपटान प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रेलवे परिसरों में गहन निरीक्षण किए गए। अधिकारियों और मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा स्वच्छता और स्वच्छ खाद्य हैंडलिंग प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए लगभग 100 फूड स्टॉल, फूड कार्ट, क्लाउड किचन और भंडारण क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। खानपान कर्मचारियों के बीच स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 200 से अधिक कैंटीन धारकों, रसोइयों और खाद्य विक्रेताओं की चिकित्सा और स्वच्छता जांच की गई। गतिविधि के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता और सुरक्षित खाद्य हैंडलिंग प्रथाओं पर जागरूकता भी बढ़ाई गई। बर्तन सफाई प्रक्रियाओं, कचरा निपटान प्रणाली, समग्र स्वच्छता और कर्मचारियों की चिकित्सा फिटनेस का आकलन करने के लिए रनिंग रूम, रेस्ट हाउस और कैंटीन सहित औचक निरीक्षण किए गए।

पश्चिम रेलवे द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पहल के अंतर्गत स्टेशनों, कॉलोनियों और खानपान इकाइयों में व्यापक स्वच्छता, सफाई और जागरूकता अभियान चलाए गए। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता में सुधार, सुरक्षित भोजन प्रथाओं को बढ़ावा देना और सक्रिय जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना था।

सावलकोट परियोजना को केंद्र की मंजूरी, पाकिस्तान को घेरने की तैयारी

(जीएनएस)। श्रीनगर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर लगा दिया। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए चिनाब नदी के पानी पर रोक लगा दी। ऐसे में अब एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान पर जल प्रहार की तैयारी कर ली। सिंधु जल संधि के निलंबन के बीच केंद्र ने चिनाब नदी पर सावलकोट परियोजना को मंजूरी दी है। जिससे साफ होता है कि भारत का पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश है कि पानी को लेकर पुरानी रियायतों का दौरा खत्म हो चुका है। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर 1,856 मेगावाट की सावलकोट जलविद्युत परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश की है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजना पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के निलंबन के बाद फिर से जीवित की जा रही है। लगभग चार दशकों से रुकी हुई, सावलकोट परियोजना चिनाब बेसिन में भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है और 1960 की संधि के तहत पश्चिमी नदी जल के अपने हिस्से का पूर्ण उपयोग करने के सरकार के प्रयासों का एक अहम हिस्सा है।